भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2500

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा

2500. **श्री राजेश रंजन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार सहित कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन और बिजली की अनुपलब्धता के कारण लाखों छात्र डिजिटल शिक्षा से वंचित हैं, जिसके परिणामस्वरूप शहरी और ग्रामीण छात्रों के बीच सीखने का अंतर लगातार बढ़ रहा है;
(ख) क्या सरकार ने देश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटरों और ब्रॉडबैंड की उपलब्धता का राज्य-वार कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या पीएम ई-विद्या और दीक्षा जैसी योजनाएं व्यावहारिक रूप से प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं या केवल कागजी घोषणाएं बनकर रह गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने तथा तदनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कोई ठोस समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में बिहार राज्य सहित सभी क्षेत्रों में अधिगम को सुदृढ़ करने, शिक्षा के मिश्रित तरीकों को सक्षम करने और डिजिटल पहुंच का विस्तार करने के लिए स्कूल की अवसंरचना में सुधार पर बल दिया गया है। स्कूलों में डिजिटल अंतर को कम करने और निरंतर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। यूडाइज+ 2025-2026 के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में कार्यात्मक बिजली वाले स्कूलों का प्रतिशत 95% है और बिहार राज्य में यह 99.5% है। इसी तरह, देश भर में 67.4% स्कूल इंटरनेट से जुड़े थे, जबकि बिहार में 91% स्कूल इंटरनेट से जुड़े हैं।

(ख): देश के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट का ब्यौरा, राज्य-वार **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में दिनांक 17 मई, 2020 को पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो देश भर में शिक्षा तक बहु-पद्धति पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहकार्यता करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन/प्रतिक्रिया भी देती है। पीएम ई-विद्या पहल में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल किए हैं।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक प्रतिभागी के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी) ने बहुभाषावाद को सक्षम करने के लिए मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.67 लाख से अधिक सामग्री तैयार करने में योगदान दिया है। क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध ई-सामग्री का ब्यौरा https://diksha.gov.in/data/. पर उपलब्ध है। कुल मिलाकर, दीक्षा पर छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा 2.29 करोड़ उपयोगकर्ताओं के लिए 579.41 करोड़ से अधिक अधिगम सत्र पूरे किए गए हैं। हितधारकों के पास दीक्षा पर 836 से अधिक वर्चुअल लैब्स तक पहुंच है जो उन्हें वास्तविक दुनिया के प्रयोगशाला वातावरण के सिमुलेशन में सहायता करती हैं। यह मंच ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों एक्सेस में सहायता करता है, जिससे शिक्षार्थी सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं और बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के अधिगम जारी रख सकते हैं।

(घ): ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों सहित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी और डिजिटल पहल को कार्यान्वित करता है। योजना के तहत, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत कक्षा VI से XII तक वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए निधियां प्रदान की जाती है।

भारत सरकार ने बजट 2025 में बीएसएनएल द्वारा चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है।

स्कूल शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की व्यवसायी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर समग्र कार्यक्रम, निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) शुरू किया है। इसे दीक्षा प्लेटफॉर्म पर फ़ेस-टू-फ़ेस, ऑनलाइन और मिश्रित प्रशिक्षण पद्धति के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है।

******

अनुलग्नक

"ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजेश रंजन द्वारा पूछे गए दिनांक 03.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2500 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

यूडाइज 2025-26 के अनुसार स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर सुविधा और इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता के साथ राज्यवार सरकारी स्कूलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यात्मक स्मार्ट कक्षा	कंप्यूटर सुविधा	इंटरनेट सुविधा
भारत	**323763**	**672778**	**634251**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	141	297	209
आंध्र प्रदेश	21878	30542	43736
अरुणाचल प्रदेश	511	932	644
असम	11788	42067	43775
बिहार	8892	28753	69807
चंडीगढ़	116	116	116
छत्तीसगढ	12267	28855	37748
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	290	353	353
दिल्ली	1940	2687	2688
गोवा	113	206	771
गुजरात	25025	33842	33823
हरियाणा	6638	14158	10857
हिमाचल प्रदेश	8378	12398	8973
जम्मू और कश्मीर	2783	6203	8550
झारखंड	5593	29846	20980
कर्नाटक	10728	21100	18007
केरल	3440	4795	4346
लद्दाख	356	478	395
लक्षद्वीप	33	34	34
मध्य प्रदेश	13308	57660	33859
महाराष्ट्र	47550	48518	44220
मणिपुर	385	784	813
मेघालय	166	654	2041
मिजोरम	319	2222	1690
नगालैंड	627	1775	1011
ओडिशा	16738	41243	39693

पुदुचेरी	320	419	419
पंजाब	17352	19182	17339
राजस्थान	17247	29291	45544
सिक्किम	565	767	373
तमिलनाडु	31321	37518	37242
तेलंगाना	9857	25429	19452
त्रिपुरा	1009	3042	1690
उत्तर प्रदेश	37450	113784	58512
उत्तराखंड	5791	15115	10732
पश्चिम बंगाल	2848	17713	13809

****